



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बौरवार, 24 जून, 2004/3 आषाढ़, 1926

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 24 जून, 2004

संख्या वि० स०-गवर्नमेंट बिल/1-36/2004.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)

विधेयक, 2004 (2004 का विधेयक संख्यांक 10) जो आज दिनांक 24 जून, 2004 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाजला,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का 14) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के पञ्चपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 है । संक्षिप्त नाम ।

2. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 17 में, उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— धारा 17 का संशोधन ।

"परन्तु यह कि निधि का सदस्य अपने विकल्प पर प्रवेश के समय तीन हजार रुपये के आजीवन अभिदान का एक मुश्त संदाय कर सकेगा :

परन्तु यह और कि निधि का विद्यमान सदस्य भी अपने विकल्प पर निधि की अपनी सदस्यता को, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, ऐसी शेष राशि का संदाय कर, जिससे कि उसके लेखे में कुल जमा राशि तीन हजार रुपये हो जाए, आजीवन सदस्यता में बदल सकता है ।"

3. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उप-धारा (2) का लोप किया जाएगा । धारा 21 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 22 में, "अन्य अधिवक्ताओं" शब्दों के पश्चात् "या उनके आश्रितों" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । धारा 22 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) में, "पांच" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा । धारा 26 का संशोधन ।

धारा 27
का
संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(क) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) प्रत्येक अधिवक्ता, उप द्वारा किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष दाखिल, प्रत्येक वकालतनामा पर दस रुपये की टिकट लगाएगा तथा कोई भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी किसी अधिवक्ता से तब तक कोई वकालतनामा स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि इसमें, नत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित किसी टिकट के अतिरिक्त, ऐसी टिकट न लगाई गई हो।” ; और

(ख) उप-धारा (3) में, “निधि के फायदों से सम्पूर्णतः या भागतः वंचित करेगा” शब्दों के पश्चात् “तथा इसे अधिवक्ता द्वारा अवचार समझा जाएगा” शब्द जोड़े जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का 14) हिमाचल प्रदेश राज्य में, व्यवसाय को बन्द किए जाने पर, अधिवक्ताओं के फायदे के लिए हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि के गठन का उपबन्ध करता है। वर्तमानतः निधि के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को या इसके पूर्व निधि का वार्षिक अभिदान संदत्त करना तथा किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए प्रत्येक वकालतनामा पर पांच रुपए मूल्य की टिकट लगाना भी अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विधि संघों और हिमाचल प्रदेश की विभिन्न परिषद् के सदस्यों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि,—

- (क) निधि का आजीवन सदस्य बनने हेतु उपरोक्त अधिनियम में उपबन्ध किया जाए और निधि के विद्यमान सदस्यों को आजीवन सदस्यता हेतु अपेक्षित अभिदान निक्षिप्त करके निधि के आजीवन सदस्य बनने का भी विकल्प किया जाना चाहिए ;
- (ख) अधिवक्ता कल्याण निधि में बढ़ौतरी हेतु निधि सदस्यों द्वारा वकालतनामा पर लगाए जाने वाली टिकट का मूल्य पांच रुपए से बढ़ाकर दस रुपए कर दिया जाना चाहिए और प्रत्येक अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पर दस रुपए मूल्य की टिकट लगाई जानी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए तथा उसका उल्लंघन ऐसे अधिवक्ता द्वारा अवचार बनाया जाना चाहिए और किसी भी न्यायालय को किसी अधिवक्ता से तब तक कोई वकालतनामा स्वीकृत नहीं करना चाहिए जब तक कि इस पर ऐसी टिकट न लगाई गई हो; और
- (ग) चिकित्सा उपचार की लागत में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत, अस्पताल में दाखिल होने या शल्य चिकित्सा इत्यादि की दशा में, पांच वर्षों की अवधि के दौरान निधि में से किसी भी सदस्य को दस हजार रुपए तक की ही राशि के अनुग्रहपूर्वक अनुदान को प्रदान करने पर धारा 21 की उप-धारा (2) के अधीन न्यासी समिति पर अधिरोपित प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव किया गया है कि युक्तियुक्त अनुग्रहपूर्वक अनुदान प्रदान करना न्यासी समिति के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त अधिनियम के उपबन्धों को अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए और उक्त अधिनियम के अधीन राज्य में व्यवसाय करने वाले समस्त अधिवक्ताओं को विस्तारित फायदे करने के लिए उपर्युक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

बीरमल सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला:

तारीख..... जून, 2004

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 (1996 का 14) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

बीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

शिमला :

तारीख जून, 2004

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 10 of 2004

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND
(AMENDMENT) BILL, 2004

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (Act No. 14 of 1996).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fifth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2004.

Amendment of section 17. 2. In section 17 of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after sub-section (4), the following provisos shall be inserted, namely :—

“Provided that a Member of the Fund may at his option make one time payment of life subscription of three thousand rupees at the time of admission :

Provided further that the existing Member of the Fund may also at his option convert his membership of the Fund into life membership by making payment of the balance amount so as to credit to his account total sum of three thousand rupees within a period of two years from the date of commencement of the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund (Amendment) Act, 2004 .”

Amendment of section 21. 3. In section 21 of the principal Act, sub-section (2) shall be deleted.

Amendment of section 22. 4. In section 22 of the principal Act, after the words "other advocates", the words "or their dependents" shall be inserted.

Amendment of section 26. 5. In section 26 of the principal Act, in sub-section (1), for the word "five", the word "ten" shall be substituted.

6. In section 27 of the principal Act,—

Amendment
of
section 27.

- (a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

“(1) Every Advocate shall affix a stamp of rupees ten on every Vakalatnama filed by him before any court, tribunal or authority and no court, tribunal or authority shall accept any Vakalatnama from an Advocate unless it is so stamped in addition to any stamp required under any other law for the time being in force.”; and

- (b) in sub-section (3), after the words “to the benefits of the Fund”, the words “and shall be deemed to be a misconduct on the part of an Advocate” shall be added.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (Act No. 14 of 1996) provides for the constitution of a welfare fund for the benefit of Advocates on cessation of practice in the State of Himachal Pradesh. Presently every Member of the Fund is required to pay annual subscription to the Advocates Welfare Fund on or before 31st March every year and also required to affix a stamp of the value of Rs. 5/- on every Vakalatnama filed by him before any court, tribunal or authority. The various Bar Associations of Himachal Pradesh and the Members of the Bar Council of Himachal Pradesh have requested the State Government that,—

- (a) a provision should be made in the Act *ibid* for becoming life time Member of the Fund and the existing Members of the Fund should also be given an option to become life time Member of the Fund by depositing requisite subscription ;
- (b) the value of the stamp to be affixed by the Members of the Fund on Vakalatnama should be enhanced from Rs. 5/- to Rs. 10/- in order to increase Advocates Welfare Fund and it should be made mandatory to affix the stamp of the value of Rs. 10/- on Vakalatnama by every Advocate and violation thereof should be made misconduct on the part of such Advocate and no court should accept any Vakalatnama from an Advocate unless it is so stamped ; and
- (c) the restriction imposed under sub-section (2) of section 21 on the Trustee Committee to grant Ex-gratia upto ten thousand rupees during a period of five years, in the case of hospitalization or surgery etc., to a Member from the Fund, should be removed in view of rising cost of medical treatment. Now it has been proposed that it should be left to the discretion of the Trustee Committee to give reasonable Ex-gratia grant.

In order to make the provisions of the Act *ibid* more effective and comprehensive and to extend the benefits under the said Act to all the Advocates practising in the State, it has been decided to make suitable amendments in the Act *ibid*. This has necessitated the amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :

The June, 2004

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

THE HIMACHAL PRADESH ADVOCATES WELFARE FUND (AMENDMENT)
BILL, 2004

BILL

to amend the Himachal Pradesh Advocates Welfare Fund Act, 1996 (Act No. 14 of 1996).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

— — — — —
SURINDER SINGH THAKUR,
Secretary (Law).

SHIMLA :
The June, 2004